भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 328
20 जुलाई, 2022 को उत्तरार्थ

राष्ट्रीय सहकारी समितियों का डेटाबेस

328. डॉ. फौजिया खान:

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस स्थापित करने की योजना है;
(ख) इसके लिए आवंटित, जारी और खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या आबंटित निधियों को जारी करने में कोई विलम्ब हुआ है; और
(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) से (घ): जी हां। देश में सहकारी आंदोलन को सर्वस्पर्शी और समावेशी बनाने के लिए; और उचित नीतिगत हस्तक्षेपों के लिए, भारत सरकार द्वारा राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों, राष्ट्रीय सहकारी संघों और अन्य सभी हितधारकों के साथ विभिन्न स्तरों पर परामर्श से एक राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस स्थापित करने की योजना है।

इस कार्य को सम्पन्न करने के लिए आवश्यकता अनुसार निधि आवंटन और उसका निर्गमन मंत्रालय के समग्र बजट से सरलता पूर्वक किया जा सकता है।

*****